'कोड वर्ड' में छिपा है विकास का रहस्य

हर प्रखंड से हर दिन कोड वर्ड में मिल रही योजनाओं की अपडेट जानकारी

अतुल उपाध्याय

पटना

विकास = कोड वर्ड

डीए: वैसे छात्र जिन्हें पोशाक योजना के तहत पोशाक मिली

जेबी: जननी बाल सुरक्षा योजना

पीटी: अस्पतालों में कितने मरीज देखे गए

टीआर: इसका इस्तेमाल प्रखण्ड में इंदिरा आवास के टार्गट के लिए

सीए : वैसे छात्र जिन्हें साइकिल योजना के तहत साइकिल दी गई है

बिहार में 'कोड वर्ड' की अपनी ही दुनिया है। सच पूछिए तो इन्हीं कोड वर्ड में विकास का रहस्य भी छिपा है। बिहार में शायद कम लोग ही यह जानते होंगे कि पूरा सरकारी सिस्टम निर्धारित कोर्ड वर्ड के जरिए विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में जुटा है।

डीए का मतलब आम लोग महंगाई भत्ता ही समझते हैं। लेकिन बिहार में चल रही योजनाओं ने इसका मायने बदल दिया है। डीए नया कोड वर्ड है। इसका अर्थ है वैसे छात्र जिन्हें पोशाक योजना के तहत पोशाक बांटी गई। इसी तरह डीबी का मतलब इसी योजना के तहत छात्राओं के अर्थ में है। सीए का अर्थ चार्टड एकाउंटेंट नहीं बल्कि वैसे छात्र जिन्हें साइकिल योजना के तहत साइकिल दी गई है।

इसी तरह जेबी का अर्थ जननी बाल सुरक्षा योजना है और पीटी का अर्थ अस्पतालों में कितने मरीज देखे गए। टीआर कोड का इस्तेमाल प्रखंड में इंदिरा आवास के टारगेट से है। दरअसल ऐसे कोड वर्ड का इस्तेमाल राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरू किए गए एसएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हो रहा है। राज्य के सभी प्रखंड इस सिस्टम से जुड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और दूसरे कई विभागों से संबंधित अफसर अपने-अपने मोबाइल से विभाग की योजनाओं की प्रगति के आंकड़ों को एक खास नंबर पर एसएमएस करते हैं। यह काम उन्हें हर दिन करना है। अफसर 24 घंटे की रिपोर्ट कोर्ड वर्ड में एसएमएस के जरिए भेज रहे हैं। यह सिस्टम पिछले कई महीनों से काम कर रहा है।

बक्सर जिले के एक प्रखंड के पीएचसी प्रभारी ने 31 दिसंबर को भेजी अपनी रिपोर्ट के बारे में कहा कि एमडी 30 का मतलब अस्पताल में तीस प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। खासबात यह है कि ऐसे कोर्ड वर्ड के इस्तेमाल के लिए प्रखंडों में विभागों को भी अलग-अलग कोड वर्ड दिया गया है।

मसलन बाढ़ से पोशाक और साइकिल से संबंधित रिपोर्ट में ब्लॉक के लिए बीएल12 का इस्तेमाल किया गया है। यह सिस्टम कितनी मजबूती से काम कर रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष के अंतिम शुक्रवार को लगभग सभी प्रखंडों से संबंधित विभागों की योजनाओं की रिपोर्ट एसएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम पर उपलब्ध थी। एसएमएस भेजने वाले अफसरों के मोबाइल नंबर भी रिपोर्ट में उपलब्ध होते हैं ताकि गड़बड़ी की सूरत में उनकी पहचान कर संपर्क किया जा सके।